पल्स पोलियो कार्यक्रम: उन्मूलन के प्रयास

भारत 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआईडी), जिसे आमतौर पर पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, 1995 में शुरू किया गया था और 2017 तक यह प्रत्येक साल के शुरुआती भाग में दो बार आयोजित किया जा रहा था। पोलियो पर इंडिया एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप (आईईएजी) की सिफारिश के अनुसार, 2018 से यह प्रत्येक वर्ष के शुरुआती भाग में एक बार आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एसएनआईडी) के कई दौर उच्च जोखिम वाले राज्यों / क्षेत्रों में वर्षों से आयोजित किए जा रहे हैं। 2017 से, देश द्वारा उच्च जोखिम वाले राज्यों/क्षेत्रों में वर्ष के जून-नवंबर महीनों के दौरान एसएनआईडी के दो दौर आयोजित हो रहे हैं। इन अभियानों में 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों को मुख से पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। प्रत्येक एनआईडी के दौरान 160 मिलियन और एसएनआईडी में 70 मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जाता है।
पोलियो वायरस संचरण का पता लगाने के लिए निगरानी प्रयोगशाला नेटवर्क के साथ 1997 से तीव्र फ्लेसीड पक्षाघात (एएफपी) के माध्यम से निगरानी की जा रही है। देश में ~ 50,000 रिपोर्टिंग साइटें हैं जो हर साल 30,000 - 40,000 एएफपी मामलों की रिपोर्ट करती हैं। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पांच वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को मुख से पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स सहित निष्क्रिय पोलियोवायरस वैक्सीन (एफआईपीवी) की आंशिक खुराक भी प्रदान की जा रही है।

प्रगति

1. डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र, जिसमें भारत शामिल है, को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था।
2. डब्ल्यूएचओ ने 24 फरवरी 2012 को भारत को "सक्रिय पोलियोवायरस संचरण वाले स्थानिक देशों" की सूची से हटा दिया।
3. भारत में आखिरी पोलियो मामला पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से 13 जनवरी, 2011 को दर्ज किया था। भारत 11 वर्षों से पोलियो मुक्त स्थिति बनाए हुए है।

देश में आखिरी बार वाइल्ड पोलियोवायरस (डब्ल्यूपीवी) का दर्ज मामला

वाइल्ड पोलियो वायरस के प्रकार	अंतिम मामले की तिथि	स्थान
पी1	13 जनवरी 2011	हावड़ा (पांचला), पश्चिम बंगाल
पी2	24 अक्टूबर 1999	अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
पी 3	22 अक्टूबर 2010	पाकुड़ (पाकुर), झारखंड

4. पल्स पोलियो कार्यक्रम (एनआईडी) के सफल कार्यान्वयन में 24 लाख टीकाकरणकर्ता और 1.5 लाख पर्यवेक्षक शामिल हैं।

5. पिछले 16 वर्षों के दौरान डब्ल्यूपीवी मामलों की कुल संख्या और प्रभावित जिलों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	**वाइल्ड पोलियो वायरस के मामले**	**जिलों की संख्या**
2005	66	35
2006	676	114

2007	874	99
2008	559	90
2009	741	56
2010	42	17
2011	01	1
2012 – 2022*	00	00*

*27 अगस्त 2022 तक के आंकड़े

भारत में पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- प्रत्येक वर्ष उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय पोलियो दौरों के माध्यम से सामुदायिक प्रतिरक्षा बनाए रखना।
- वाइल्ड पोलियोवायरस और वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियोवायरस (वीडीपीवी) के किसी भी आगमन या संचलन के लिए देश भर में एएफपी निगरानी के माध्यम से अत्यधिक उच्च स्तर की सतर्कता बरती जा रही है। यहां तक की कोविड -19 महामारी के दौरान, एएफपी निगरानी संवेदनशीलता वैश्विक अनुशंसित स्तरों से ऊपर रही।
- पोलियो वायरस संचरण का पता लगाने के लिए पर्यावरण निगरानी (सीवेज नमूनाकरण) स्थापित किया गया है और प्रगति के एक सरोगेट संकेतक के रूप में और साथ ही किसी भी प्रोग्रामेटिक हस्तक्षेप के लिए स्थापित किया गया है। देश में रणनीतिक रूप से 13 राज्यों - असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 60 पर्यावरण निगरानी स्थल हैं।
- देश में आठ विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं जो कसौली, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में स्थित हैं। इन सभी प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन विश्व स्तर पर अनुशंसित लक्ष्यों से अधिक है। ये प्रयोगशालाएं देश में वाइल्ड पोलियोवायरस या वीडीपीवी के संचरण का पता लगाने के लिए सालाना 60,000 से 80,000 मल के नमूनों और ~ 1500 सीवेज के नमूनों की जांच करती हैं।
- देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने देश में किसी भी पोलियो प्रकोप से निपटने के लिए एक शीघ्र अनुक्रिया दल (आरआरटी) विकसित किया है। देश में आपात तैयारी और अनुक्रिया योजना (ईपीआरपी) भी विकसित की गई है जिसमें पोलियो के मामले का पता लगने पर उठाए जाने वाले कदमों का विवरण दिया गया है।
- पड़ोसी देशों से आगमन के जोखिम को कम करने के लिए, सभी पात्र बच्चों को निरंतर टीकाकरण टीमों (सीवीटी) के माध्यम से चौबीसों घंटे अंतरराष्ट्रीय सीमा टीकाकरण प्रदान किया जा रहा है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थापित विशेष बूथों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। 31 अगस्त 2022 तक लगभग 1.5 करोड़ बच्चों को ओपीवी का टीका लगाया जा चुका है।
- भारत सरकार ने भारत और अन्य प्रभावित देशों जैसे अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, सीरिया और कैमरून की यात्रा के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पोलियो टीकाकरण की अनिवार्य आवश्यकता के लिए मार्च 2014 से प्रभावी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- ओपीवी का एक रोलिंग आपात स्टॉक वाईल्ड पोलियो वायरस (डब्ल्यूपीवी) का पता लगने/आगमन या परिसंचारी वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियोवायरस (सीवीडीपीवी) के उद्भव होने पर अनुक्रिया देने के लिए रखा जा रहा है।
- टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की सिफारिश के अनुसार, देश में पोलियो एंडगेम रणनीति और टीओपीवी- बीओपीवी स्विच के तहत 2015 की अंतिम तिमाही में पेंटवालेंट वैक्सीन की तीसरी खुराक के साथ साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में इंजेक्शन के द्वारा दी जाने वाली इनएक्टिवेटेड पोलियो वाइरस वैक्सीन (आइपीवी) की शुरुआत की गई है।

- 25 अप्रैल 2016 को देश ने सफलतापूर्वक टीओपीवी वैक्सीन के स्थान पर बीओपीवी वैक्सीन शुरू की। यह डब्ल्यूएचओ द्वारा टाइप 2 डब्ल्यूपीवी के उन्मूलन की घोषणा और ओपीवी के टाइप 2 घटक के कारण वीडीपीवी के जोखिम को कम करने के मद्देनजर किया गया था।
- 2017 में, भारत ने नियमित टीकाकरण में निष्क्रिय पोलियोवायरस वैक्सीन (आईपीवी) की आंशिक खुराक की शुरुआत की। 6 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र वाले बच्चो को मौखिक पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) की पहली और तीसरी खुराक के साथ एफआईपीवी की दो खुराकें भी दी गईं।
- कोविड-19 महामारी ने टीकाकरण कवरेज के साथ-साथ एएफपी निगरानी संवेदनशीलता को भी प्रभावित किया। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियमित टीकाकरण, पल्स पोलियो चक्र और निगरानी गतिविधियों पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।एएफपी मामलों की रिपोर्ट करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के टेलीफोनिक संवेदीकरण की अवधारणा को 2020 में पेश किया गया था। एएफपी निगरानी और नमूना संग्रह पर ऑडियोविज़ुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना के व्यापक प्रसार के लिए विकसित किए गए हैं।

2001-2022 के दौरान पोलियो मामलों की संख्या (27 अगस्त 2022 तक)

वाइल्ड पोलियोवायरस मामले													
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 - 2021	2022*
पश्चिम बंगाल	1	49	28	2	0	1	2	2	0	8	1	0	0
उत्तर प्रदेश	216	1242	88	82	29	548	341	305	602	10	0	0	0
बिहार	27	121	18	39	30	61	503	233	117	9	0	0	0
झारखंड	2	12	1	0	2	1	0	0	2	8	0	0	0
महाराष्ट्र	4	6	3	3	0	5	2	2	0	5	0	0	0
हरियाणा	5	37	3	2	1	19	6	2	4	1	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
दिल्ली	3	24	3	2	1	7	2	5	4	0	0	0	0
पंजाब	5	2	1	0	1	8	1	2	4	0	0	0	0
उत्तराखंड	3	14	0	1	1	13	6	1	4	0	0	0	0
राजस्थान	0	41	4	0	0	1	3	2	3	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
ओड़ीसा	0	4	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	0	19	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0
तेलंगाना	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	21	11	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
असम	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
गुजरात	1	24	3	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	0	0	36	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दा॰ और न॰ हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**268**	**1600**	**225**	**134**	**66**	**676**	**874**	**559**	**741**	**42**	**1**	**0**	**0**